बजट में आर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू करने की घोषणा

आर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देगी सरकार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

चेन्नई. राज्य विधानसभा में कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को घोषणा की कि तमिलनाडु जैविक खेती मिशन को बागवानी विभाग द्वारा 50 हेक्टेयर के क्लस्टर आकार के साथ प्रत्येक जिले में दो समूहों के साथ क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण पर लागू किया जाएगा।

वर्ष 2022-23 का कृषि बजट पेश करते हुए मंत्री ने कहा, यह विशेष प्रशिक्षण और एक्सपोजर यात्राओं के माध्यम से खेती के तरीकों पर जागरूकता पैदा करने, मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने, जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयों पर सलाह देने और वितरण के बारे में प्रचार गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कोष से 30 करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन के परीक्षण के लिए एक अवशिष्ट विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला का निर्माण, जैविक प्रमाणन विभाग के साथ पंजीकरण आदि किए जाएंगे। साथ ही पशुशाला और वर्मी कम्पोस्ट इकाई के समन्वय से स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने कहा किसानों के लिए उच्च उपज, सूखा सहिष्णु और बाढ़ प्रतिरोधी बीजों का उत्पादन करके पैदावार बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है।

विल्लुपुरम और तिरुपुर जिलों में एकीकृत बीज प्रमाणन कार्यालय परिसर- गुणवत्ता वाले बीजों तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए और किसानों को बीज उत्पादन और जैविक प्रमाणन पर सलाह देने के लिए बीज प्रमाणन, बीज निरीक्षण और बीज परीक्षण को समायोजित करने के लिए एकीकृत बीज प्रमाणन कार्यालय परिसर विल्लुपुरम और तिरुपुर जिलों में 4 करोड़ रुपए के परिव्यय पर स्थापित किया जाएगा। साथ ही किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को जैविक उत्पादों के अवशेष विश्लेषण की लागत के लिए 100 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। इसके लिए सालाना 12.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की जाएगी।

तमिलनाडु का पहला पूर्ण कृषि बजट पेश करने से पहले कृषि मंत्री एमआरके पनीरसेल्वम ने मुखयमंत्री से शुभकामना प्राप्त की। दूसरे चित्र में विधानसभा में कृषि बजट पेश करते कृषि मंत्री एमआरके पनीरसेल्वम।

स्पेक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया

इसके एक हिस्से के रूप में बीज प्रमाणन गतिविधियों को तेज और पारदर्शी तरीके से करने के लिए किसानों और बीज उत्पादकों को वास्तविक समय में सेवा देने को स्पेक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के तहत जैविक प्रमाणन की गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया जाएगा। 2021-22 के दौरान बीज प्रमाणन एवं जैविक प्रमाणन विभाग और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बीज उत्पादन तकनीकों पर 100 स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया गया था। इस दौरान मांग के आधार पर अधिकाधिक स्वयं सहायता समूहों को कपास, बाजरा आदि में बीज उत्पादन पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

भागीदारी गारंटी प्रणाली शुरू की जाएगी- जैविक किसान अपने जैविक रूप से उगाए गए प्रमाणीकरण और विपणन के लिए महत्वपूर्ण खर्च करते हैं। इसलिए बिना किसी प्रमाणन शुल्क के राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों के विपणन की सुविधा के लिए भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) शुरू की जाएगी। तमिलनाडु सरकार कृषि के डिजीटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही नवीनतम सॉफ्टवेयर पेश कर रही है।

33007 करोड़ रुपए का कृषि बजट पेश

चेन्नई. कृषि और किसान कल्याण मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को वर्ष 2022-23 का 33,007 करोड़ रुपए का पहला पूर्ण कृषि बजट पेश किया। बजट में फसल ऋण और अन्य विकास योजनाओं को लेकर व्यापक घोषणाएं और बजट आवंटन हुआ। पेश हैं भाषण के प्रमुख अंश...

- 3204 गांवों में 300 करोड़ की लागत से सर्व ग्राम अण्णा मरुमलारची योजना
- शुष्क भूमि मिशन के लिए 132 करोड़ रुपये
- प्रीमियम सब्सिडी के लिए 2,399 करोड़ रुपये
- 60,000 किसानों को 5 करोड़ रुपये की सब्सिडी से तिरपाल
- 9 करोड़ रुपये की लागत से नारियल विकास योजना
- छोटे और सीमांत किसानों को मौजूदा सब्सिडी दर के अलावा 20 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी की अनुमति
- कृषि क्लिनिक या कृषि आधारित गतिविधियों की स्थापना के लिए 200 बेरोजगार कृषि या बागवानी इंजीनियरिंग स्नातकों को एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता
- महिलाओं की दैनिक आय बढ़ाने के लिए फूलों की खेती को 4,250 एकड़ में बढ़ाया जाएगा
- उळवर संदै का नवीनीकरण और स्थापना, धर्मपुरी, नागपट्टिनम, वेलूर और तिरुपत्तूर जिलों में कुल 10 करोड़ रुपये की लागत से 4 नए उळवर संदै की स्थापना।